विनायक नारायण देवस्थली

बनाम

केंद्रीय जांच ब्यूरो

(की आपराधिक अपील संख्या 335/2005)

12 जनवरी, 2015

[सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय और एन. वी. रमना, जे. जे.]

दंड संहिता,1860-धारा 409 / 120-बी, 403, 477-ए 109- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988- धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(डी) - सुरक्षा घोटाला - अपीलकर्ता-अभियुक्त का अभियोजन (बैंक कर्मचारी) के साथ आपराधिक साजिश रचने के लिए कुख्यात शेयर-ब्रोकर (आरोपी नंबर 3-हर्षद मेहता) के साथ इसका उद्देश्य बैंक को धोखा देना और अवैध लाभ प्राप्त करना है अभियुक्त संख्या 3 - विशेष न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि - अपील पर, आयोजित अपीलकर्ता-अभियुक्त साजिश का हिस्सा था एसजीएल (सहायक जनरल1-एजर) के व्यापार को सुविधाजनक बनाना अभियुक्त संख्या 3 का दुरुपयोग करके उसके लाभ के लिए प्रतिभूतियाँ आधिकारिक स्थिति और बैंकिंग कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन करके - अभियोजन ने सफलतापूर्वक दस्तावेजी साक्ष्य से अपराध को उचित संदेह से परे साबित कर दिया।

न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया गया :-

1. एस. जी. एल. (सब्सिडियरी जनरल लेजर) से निपटने की प्रक्रिया जैसा कि पीडब्लू 1 और पीडब्लू2 द्वारा समझाया गया है विचाराधीन प्रतिभूतियाँ के मामले में का पालन नहीं किया गया है। अभिलेख पर सामग्री स्पष्ट रूप से यह स्थापित करता है कि यूको बैंक एसजीएल खाता संख्या 065 के खाते में हुई त्रुटि के परिणामस्वरूप हर्षद मेहता (अभियुक्त संख्या 3) को लाभ हुआ वह गलत प्रविष्टि एक अनजाने में नहीं हुई थी, बल्कि दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया एक सुनियोजित कुकर्म था। अपीलार्थी अभियुक्त, जो बैंकिंग गतिविधियों से अच्छी तरह से परिचित है और एस. जी. एल. लेनदेन, झूठे दस्तावेज बनाए गए जाँच का आधार और प्रावधानों के विपरीत कार्य कर और अवैध कार्य जो अभिलेख के सामने बड़े पैमाने पर लिखे जाते हैं, प्रतिबद्ध किया। इस प्रकार, अपीलार्थी एस. जी. एल. प्रतिभूतियों के व्यापार को सुविधाजनक बनाने की साजिश का हिस्सा था। अभियुक्त नंबर 3 और इस प्रक्रिया में, अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और बैंकिंग कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन किया। मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से आपराधिक कृत्यों में अपीलार्थी की भागीदारी और अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करना को दर्शाती हैं। अभियोजन पक्ष ने आरोपी के बीच सांठगांठ को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है। जिन अपराधों के लिए अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है, उनकी सामग्री को अभियोजन पक्ष द्वारा बडे पैमाने पर दस्तावेजी साक्ष्य के साथ-

साथ मौखिक साक्ष्य जोडकर सभी उचित संदेह से परे स्थापित किय गया है। (पैरा 29 और 30)(98-ई-एचय 99-बी-डी)

2. टेलेक्स संदेश दिनांक 23.3.1991 (विस्तार 287) और 6.4.1991 (विस्तार 466) से पता चलता है कि यूको बैंक प्रधान कार्यालय अपने स्वयं के खाते (032) के लिए स्पष्ट रूप से निर्देश दिया। आरोपी नंबर 1 और 2 द्वारा भेजा गया पत्र दिनांक 13 अप्रैल 1991 (विस्तार 300) को परिणामी घटनाओं पर विचार करने में साधारण गलती नहीं माना जा सकता। उक्त संचार की तैयारी और प्रश्नगत प्रतिभूतियों के संबंध में प्रविष्टि भी आरोपी नंबर 1-अपीलकर्ता स्वयं लिखा गया हैं। यह प्रविष्टि प्रतिभूतियों को यूको बैंक क्रमांक 065 (दलालों का खाता) के खाते में स्थानांतरित करने के लिए दो अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित प्रविष्टियों के साथ जो वास्तव में थीं, यूको बैंक के खाता संख्या 065 में स्थानांतरण के लिए इंगित करती है। अतरू यह नहीं कहा जा सकता कि यह मात्र एक लिपिक गलती हुई कि खाता संख्या 032 काट दिया गया और खाता संख्या 065 आरोपी संख्या 2 द्वारा रखा गया था। अपीलकर्ता द्वारा उक्त संचार में प्रश्नगत प्रतिभूतियों का समावेश अपनी लिखावट में, इस तथ्य को स्थापित करता है कि अपीलकर्ता ने जानबूझकर और गलत इरादे से संचार तैयार कर ऐसा किया था (पैरा 27)(97-सी-जी)

3. 2 करोड रुपये की राशि का खाता नम्बर 065 से खाता नम्बर 032 मे बिना किसी लेन-देन के हस्तांतरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मुख्य कार्यालय की पूछताछ से दूर रहने के लिए, अभियुक्त ने बिना किसी लेन-देन के पैसे ट्रांसफर करना चुना है जो अभियुक्त के आचरण को प्रदर्शित करता है। लेन-देन बदलने से संबंधित लगभग सभी दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर हैं। (पैरा 28)(97-जी-एच; 98-ए-बी)

आपराधिक अपील न्याय निर्णयः आपराधिक अपील सं. 335/2005

बॉम्बे विशेष न्यायालय (लेन-देन से संबंधित अपराधों का मुकदमा) के विशेष मामला संख्या 3/1995 मे पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 03.12.2004 से ।

धीरज मिराजकर, कामिनी जैसवाल अपीलार्थी की ओर से

विभा दत्ता मखीजा, टी. ए. खान, चेतन चावला, दिशा वैश्य, बी. वी. बलरामदास, अरविंद कुमार शर्मा उत्तरदाता के लिए ।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश एन. वी. रमना, जे. द्वारा पारित किया गया :-

1. यह अपील विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित अपराधों का परीक्षण) बॉम्बे का 3 दिसंबर, 2004 का निर्णय 1995 का विशेष मामला सं. 3 के खिलाफ निर्देशित है जिसके द्वारा विशेष न्यायाधीश अपीलार्थी द्वारा धारा 409/120बी,403, 477-ए/109, आईपीसी और धारा

13 (2) के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (डी) के साथ पढ़ें।

2. अभियोजन पक्ष की संक्षेप में कहानी, यह है कि वर्ष 1991 के दौरान, अपीलार्थी (आरोपी संख्या 1) जब वह यूसीओ बैंक हमाम स्ट्रीट शाखा, मुंबई के प्रतिभूति विभाग में सहायक प्रबंधक के रूप में काम कर रहा था, उसने अपने एक बैंक के सहयोगी (आरोपी नंबर 2) के साथ मिलीभगत कर उस समय के बॉम्बे के कुख्यात शेयर और स्टॉक ब्रोकर हर्षद एस. मेहता (आरोपी संख्या 3) के साथ यूको बैंक को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाकर धोखाधड़ी कर और आरोपी संख्या 3 (हर्षद मेहता) को अवैध लाभ पहुंचाने के उद्देश्य आपराधिक षड्यंत्र रचा। यह आरोप लगाया जाता है कि अपीलार्थी लोक सेवक होने के बावजूद उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और गैरकानूनी सुविधा के लिए खातों में हेरफेर करके बैंक के धन का दुरुपयोग कर हर्षद एस. मेहता (आरोपी संख्या 3) को लाभ पहुंचाने के लिए विश्वास का आपराधिक उल्लंघन किया।

3. मामले की पृष्ठभूमि में अभियोजन पक्ष का कहना है कि प्रासंगिक समय में, यूको बैंक के भारतीय रिजर्व बैंक में दो सहायक सामान्य खाता (एसजीएल) थे। एसजीएल केन्द्र सरकार द्वारा जारी एक प्रकार का प्रतिभूति खाता है। इन प्रतिभूतियों में लेनदेन करने के लिए बैंकों और वित्तीय

संस्थानों को भारतीय रिजर्व बैंक के सार्वजनिक ऋण कार्यालय के साथ एसजीएल खाता खोलना होगा। यूको बैंक के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऐसे दो एसजीएल खाते हैं। यूको बैंक के स्वामित्व वाले दो एसजीएल खातों में से, 032 नंबर वाला एक खाता बैंक के मुख्य कार्यालय के अपने लेनदेन के लिए और दूसरा एसजीएल खाता संख्या 065 घटकों/दलाल द्वारा किए गए लेनदेन के लिए रखा गया था। जब बैंक स्वयं सरकारी प्रतिभूति खरीदी/बेची थी, तो संबंधित प्रविष्टि खाता संख्या 032 में की जानी थी। यदि प्रतिभूति किसी दलाल ग्राहक द्वारा खरीदी/बेची गई थी, तब यूको बैंक के एस. जी. एल. खाता संख्या 065 में प्रविष्टि की जानी थी। जहाँ तक आर. बी. आई. की पुस्तकों में प्रविष्टि का संबंध था, यूको बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार दोनों खाते यूको बैंक के नाम पर होने की स्थिति में प्रत्येक लेनदेन के लिए इंद्राज एक विशेष खाते में किया गया था।

4. 22 मार्च, 1991 को यूको बैंक ने अपने एस. जी. एल. खाता संख्या 032 से भारत सरकार 11.5 प्रतिशत 2009, मूल्य 20 करोड रूपये की प्रतिभूतियाँ भारतीय बैंक (एक्स. 250) को बेच दीं। उसी दिन यूको बैंक द्वाराभारत सरकार 11.5 प्रतिशत 2006, मूल्य 20 करोड की प्रतिभूतियाँ इंडियन बैंक (एक्स.टी. 425) से खरीदी गई।

5. 5 अप्रैल, 1991 को यूको बैंक ने पहले बेची गयी जीओआई 11.5 प्रतिशत 2009 प्रतिभूतियाँ इंडियन बैंक से फिर खरीद ली और पहले

खरीदी गई जीओआई 11.5 प्रतिशत 2006 प्रतिभूतियाँ इंडियन बैंक को बेच दीं। दूसरे शब्दों में, यूको बैंक ने पहले के लेनदेन को उलट दिया। आर. बी. आई. द्वारा यूको बैंक की पुनर्खरीद का यूको बैंक के एसजीएल खाता संख्या 032 में प्रतिभूतियों के मूल्य को जमा करते हुए प्रविष्टि होनी चाहिए।

6. जबकि, 13 अप्रैल 1991 (एक्स. 300) को एक संचार के कारण, अपीलार्थी अभियुक्त द्वारा अपने स्थान पर हस्ताक्षरित सहायक लेखाकार और सह-अभियुक्त (वर्तमान अपील में पक्षकार नहीं) के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक से एस. जी. एल. में प्रवेश करने का अनुरोध करते हुए खाता सं. डी. वी. एस. एल. 065, एस. जी. एल. खाता संख्या 065 जो यूको बैंक के दलाल ग्राहकों के लिए था और जिसके पास था उस तारीख को कोई शेष राशि नहीं थी, जिसमें 20 करोड़ की प्रतिभूतियों की शेष राशि दिखाई गई। उस समय अन्य सभी लेन-देन अभियुक्त सं. 3 (हर्षद मेहता) के संबंध को छोड़कर दलाल आपस में भिड़ गए। इस गलत प्रविष्टि को अपने लाभ में लेते हुए, आरोपी नंबर 3-हर्षद एस. मेहता, के दलालध्ग्राहक होने के नाते यूको बैंक ने जी. ओ. आई. प्रतिभूतियाँ 11.5 प्रतिशत 2009 बेचीं, जिनकी कीमत 15 करोड़ (ई.एक्स.टी. 413), जो वास्तव में उसका नहीं था, और इस तरह गलत तरीके से प्राप्त हुआ और यूको बैंक को नुकसान उठाना पड़ा। यह कोई और नहीं बल्कि अपीलार्थी-अभियुक्त संख्या 1 था, जिसने संबंधित डेबिट और क्रेडिट वाउचर पारित किए लेन-देन

(ई.एक्स.टी. 29,296-297) जब ये गलतियाँ होती हैं पता चला कि आरोपी ने कदम उठाए और लेन-देन को छिपाने का प्रयास किया।

7. जब वर्ष 1992 में प्रतिभूति घोटाला सामने आया, मामलों से निपटने के लिए सी. बी. आई. द्वारा एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी। घोटाले से उत्पन्न होना। तदनुसार, आरोपी के खिलाफ 30 दिसंबर, 1993 को आई. पी. सी. की धारा 409, 420, 468, 471, 477-ए के साथ पठित धारा 120 बी का उपयोग करते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और पी. सी. अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (डी) के साथ पठित धारा 13 (2) और मामला विशेष न्यायालय को सौंप दिया गया। अपीलार्थी को 12 मई, 1997 को गिरफ्तार किया गया था। विशेष न्यायाधीश ने मामले को समग्र रूप से देखने के बाद अपीलार्थी को दोषी ठहराया अपराधों के बारे में और उन्हें कठोर सजा सुनाई गई। एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास और राशि का भुगतान करने के लिए से रु. 25,000/- जुर्माने की प्रति, उसकी चूक में, तीन महीने की अवधि के लिए और कारावास से गुजरना होगा। विशेष न्यायाधीश, तथापि, अभियुक्त अपीलार्थी को 12 सप्ताह की अवधि के लिए जमानत पर रहने दें ताकि वह अपीलीय न्यायालय का रुख कर सके।

8. विशेष न्यायाधीश के फैसले से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने विशेष अदालत की धारा 10 के तहत यह अपील दायर की। न्यायालय

(प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अपराधों का परीक्षण) अधिनियम, 1992। इस तरह यह अपील हमारे सामने है।

9. हालाँकि इस मामले में तीन आरोपी हैं, लेकिन हम केवल आरोपी नंबर 1-अपीलार्थी से संबंधित हैं। अन्य दो आरोपी मकरंद वसंत सिद्धाये (आरोपी नंबर 2) और हर्षद एस. मेहता (आरोपी नंबर 3) इस मामले में पक्षकार नहीं हैं। वर्तमान अपील। हालांकि, यह उल्लेख करना उचित है कि मकरंद वसंत सिद्धाये (आरोपी नंबर 2) ने भी प्राथमिकता दी थी। विशेष के फैसले के खिलाफ इस न्यायालय के समक्ष अपील न्यायाधीश 2005 की आपराधिक अपील संख्या 336 है जिसे सूचीबद्ध किया गया था 11 नवंबर, 2014 को इस न्यायालय के समक्ष जब निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

2005 की आपराधिक अपील संख्या 336

यह अपील आम लोगों के खिलाफ सूचीबद्ध है आपराधिक अपील सं. 335/2005 के साथ निर्णय।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील उपस्थित नहीं है।

यह अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा बार में सूचित किया जाता है। आपराधिक अपील सं. 335/2005 में कि मकरंद वसंत सिद्धाये-आपराधिक अपील सं. 336/2005 में अपीलार्थी की मृत्यु हो गई। हमारे ध्यान में लाए

जाने पर, अपील को निरस्त कर दिया जाता है और उसका निपटारा कर दिया जाता है।

जहाँ तक अभियुक्त संख्या 3 (हर्षद एस. मेहता) का संबंध है, वह सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट है, 31 दिसंबर, 2001 को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी।

10. 21 फरवरी, 2005 को अपील को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने निलंबित करके अपीलार्थी को इस न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान कारावास की सजा से अंतरिम राहत प्रदान की। ।

11. अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विशेष न्यायाधीश अभियुक्त को दोषी ठहराने में सही और त्रुटिपूर्ण साक्ष्य अपराधों की सराहना करने में विफल रहे। प्रतिभूतियों से संबंधित एस. जी. एल. जानकारी 5 अप्रैल, 1991 को यूको बैंक द्वारा फिर से खरीदा गया 12 अप्रैल, 1991 को। जब से वहाँ कई थे ग्राहकों दलालों द्वारा लेन-देन और पुनः खरीदी गई एस. जी. एल. जानकारी लगभग एक सप्ताह के अंतराल के बाद प्राप्त हुई। अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा प्रतिभूतियों को प्रतिभूति में जमा कराने में लिपिकीय और प्रामाणिक गलती की गई थी। यू. सी. ओ. के खाता संख्या 032 के बजाय एस. जी. एल. खाता संख्या 065 बैंक। किसी भी मामले में अभियुक्त की कोई भागीदारी नहीं थी अभियुक्त नं. 3, हर्षद मेहता को लाभ पहुँचाने की साजिश। यह था विशुद्ध रूप से एक लिपिकीय

त्रुटि जो बिना किसी बुरे इरादे के आकस्मिक तरीके से हुई। एक सामान्य तरीके से, आरोपी ने आवरण पर हस्ताक्षर किए 13 अप्रैल, 1991 के नोट पर भी आरोपी संख्या 2 द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक एस. जी. एल. खाते संख्या 065 में प्रतिभूतियों को जमा कर सकता है। अभियुक्त-अपीलार्थी की कोई दुर्भावना या बेईमानी नहीं थी यूको बैंक को कोई धोखाधड़ी करने या नुकसान पहुँचाने का इरादा या उसे धोखा देना। गलती बिना यांत्रिक रूप से हुई अपीलार्थी की सचेत भागीदारी। यह भी स्पष्ट है कि अभिलेख कि अभियुक्त सं. 2 ने स्वयं धारा 313, सीआरपीसी के तहत अपने बयान में स्वीकार किया है कि यह वही था जिसने हमला किया था। नोट (एक्स. 300) में खाता संख्या 032 और आवरण में खाता संख्या 065 लिखा। इस प्रकार, अपीलार्थी पर एक उचित लिपिकीय गलती के लिए गंभीर दंड का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

12. विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी यूको बैंक की शाखा हमाम स्ट्रीट के नियमित काम से संबंधित नहीं था। उन्हें विशेष रूप से प्रतिभूतियों का मोचन और सुलह कर्तव्य सौंपे गए थे। जबकि उन कर्तव्यों का निर्वहन, जब अपीलार्थी ने देखा गलती से, उन्होंने तुरंत रुपये के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की। 2 पर करोड़ 15 जुलाई, 1991 में खाता संख्या 065 से खाता संख्या 032 तक रिकॉर्ड को सही करने के लिए। विद्वान विशेष न्यायाधीश, इस तथ्य को सही मायने में समझने में विफल रहे हैं कि एस. जी. एल. स्थानांतरण फॉर्म (एक्स. 235 और

एक्स. 240) द्वारा बेची गई प्रतिभूतियों के संबंध में हर्षद मेहता ने एस. जी. एल. खाते से रू 15 करोड़ रुपये निकाले सं. 065, अपीलार्थी और अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थे उस लेन-देन में उनकी कोई भूमिका नहीं है। यह तथ्य स्वयं स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि अपीलार्थी किसी साजिश का हिस्सा नहीं था अभियुक्त संख्या 3 (हर्षद मेहता) के साथ। लेकिन विशेष न्यायाधीश एक अलग और गलत दृष्टिकोण लिया और यह मानते हुए गलती की कि अपीलार्थी ने खाता संख्या 065 में पड़े से खाता संख्या 032 तक 2 करोड़ रुपये मूल्य की प्रतिभूतियाँ हस्तांतरित कीं। अभियुक्त-अपीलार्थी और अभियुक्त संख्या 3 (हर्षद मेहता) के बीच संबंध स्थापित करने के लिए अभिलेख पर कोई सबूत नहीं था जो उनके और अभियुक्त के बीच साजिश रच रहा था।

13- अभियोजन पक्ष इस पहलू को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है और इसलिए, अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है। अपीलार्थी ने केवल अपने कर्तव्यों का पालन किया था आज्ञाकारी रूप से जिसके लिए उसे बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता है जैसे कि अपीलार्थी लेन-देन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था। महत्वपूर्ण कारक, जिसे विद्वान विशेष न्यायाधीश ने नजरअंदाज कर दिया, जबकि अपीलार्थी को दोषी ठहराते हुए कहा गया है कि अपीलार्थी ने अपने लिए कोई आर्थिक लाभ अर्जित नहीं किया था। विद्वत विचारण न्यायाधीश के अधीन अभियोजन पक्ष के मामले में एक गलत धारणा बनी रही। केवल

अनियमितता या लापरवाही के साधारण कारण के लिए कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, अपीलार्थी को विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा सजा की कठोर सजा दी गई थी, भले ही तथ्यात्मक रूप से यूको बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ। विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि अपीलार्थी के कृत्यों ने यूको बैंक को गंभीर वित्तीय नुकसान के लिए उजागर किया है, बिल्कुल सूक्ष्म और साक्ष्य पर आधारित नहीं है। अभियोजन पक्ष ने यह भी स्वीकार किया कि यूको बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ था। अपीलार्थी के द्वारा कल्पना का कोई भी विस्तार के कार्य नहीं हो सकते हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की परिधि उसके खिलाफ आपराधिक कदाचार का लेबल लगाने के लिए बनाया गया।

14. वाक्य की मात्रा पर भी विवाद करते हुए, सीखा अपीलार्थी के वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थी को सजा सुनाते समय इस तत्व की अनदेखी की सजा देने में आनुपातिकता। विद्वान विशेष न्यायाधीश तथ्यों की सराहना करने में बुरी तरह विफल रहे हैं उचित परिप्रेक्ष्य और अपीलार्थी को दोषी ठहराने में एक गंभीर त्रुटि की और इसलिए विवादित निर्णय में इस न्यायालय का हस्तक्षेप मांग करता है।

15. दूसरी ओर, विद्वान वरिष्ठ वकील उपस्थित हुए सी. बी. आई. के लिए, विद्वानों के निर्णय का समर्थन करते हुए विशेष न्यायाधीश ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विशेष न्यायाधीश ने पूरी तरह से कार्य करने के बाद

विवादित निर्णय पारित किया परीक्षण प्रक्रिया। वह इस निष्कर्ष पर तभी पहुंचे जब उन्हें इस बात का संतोष हुआ कि आरोपी का अपराध साबित हो चुका है उचित संदेह। अतः विचारण न्यायालय ने इसमें कोई त्रुटि नहीं की अभियुक्त को सजा सुनाए।

16. उसने तर्क दिया कि आरोपी दलील नहीं दे सकता है निर्दोषता के रूप में उन्होंने अभियुक्त सं. 3 (हर्षद मेहता) को लाभ पहुँचाने की साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई। इस प्रक्रिया में, उन्होंने यूको बैंक के एक कर्मचारी होने का लाभ उठाया, एसजीएल लेनदेन से पूरी तरह से परिचित, और प्रतिबद्ध किया अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करना। एस. जी. एल. में रू 20 करोड़ के मूल्य की 11.5 प्रतिशत सी. जी. एल. 2009 प्रतिभूतियों का हस्तांतरण भारतीय रिजर्व बैंक के सार्वजनिक ऋण कार्यालय में खाता संख्या 065 केवल अभियुक्त-अपीलार्थी के दुर्भावनापूर्ण इरादे से गलत लाभ प्रदान करने के अपने अवैध उद्देश्य के अनुसरण में प्रभावित हुआ। अभियुक्त सं. 3 (हर्षद मेहता)। अभियुक्त द्वारा रची गई साजिश ने यूको बैंक को उस ब्याज से वंचित कर दिया जो प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर उपार्जित राशि रू 20 करोड़ अवैध वस्तु और अभियुक्त विनायक नारायण देवस्थली बनाम द्वारा निभाई गई भूमिका। पूर्ण ज्ञान और इरादे के साथ लेन-देन की एक श्रृंखला द्वारा स्थापित किया जाता है जो एक निरंतर श्रृंखला और परिस्थितियों की कड़ी बनाता है जिससे आरोपी दोषी हो जाता है।

17. विद्वान परामर्श ने दिनांक 23 मार्च, 1991 का संदेश (एक्स. 287) यूको बैंक द्वारा अपने मुख्य कार्यालय से क्षेत्रीय कार्यालय को यूको बैंक मुख्य कार्यालय के पक्ष में परिवर्तन लेनदेन खाता (एस. जी. एल. खाता संख्या 032) के प्रभाव के लिए निर्देश भेजकर एक टेलेक्स की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उन स्पष्ट के बावजूद निर्देश, अभियुक्त-लाभ पहुँचाने की दृष्टि से अपीलार्थी अभियुक्त संख्या 3 ने यू. सी. ओ. में प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को प्रभावित किया बैंक घटक/दलाल खाता (खाता संख्या 065)। यह भी है अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रासंगिक समय पर, सभी दलाल अभियुक्त संख्या 3 (हर्षद मेहता) को छोड़कर लेन-देन का वर्ग किया गया था। जिन्होंने गलत तरीके से हस्तांतरित प्रतिभूतियों को अपने लाभ के लिए बेच दिया, जिससे यूको बैंक को नुकसान हुआ।

18. अवैध की उपलब्धि के अनुसरण में अभियुक्त सं. 3 को गलत लाभ पहुंचाने हेतु अपीलार्थी, सार्वजनिक नौकर होने के नाते अपने पद का काफी हद तक दुरुपयोग किया। जब यूको बैंक के मुख्य कार्यालय को उनके टेलेक्स संदेश के संदर्भ में स्विच लेनदेन के विकास के बारे में सूचित नहीं किया गया था अभियुक्त द्वारा स्वीकार किया जा रहा है, मुख्य कार्यालय 6 अप्रैल, 1991 (466) को एक और टेलेक्स संदेश जारी किया गया। लेन-देन के बारे में पूछताछ। इस दूसरे टेलेक्स के बावजूद मुख्य कार्यालय से संदेश, आरोपी ने तुरंत मुख्य कार्यालय को सूचित करने का जवाब नहीं दिया और केवल 11 अप्रैल, 1991 को आरोपी ने एक टेलेक्स संदेश भेजा (अतिरिक्त

288) से लेन-देन के निष्पादन की सूचना देने वाला मुख्य कार्यालय, वह भी सच्चाई को छिपाना। अभियुक्त के गलत इरादों को प्रदर्शित करने वाला एक अन्य लिंक यह है कि बैंक रसीद (अतिरिक्त 299) दिनांक 5 अप्रैल, 1991 को इंडियन बैंक द्वारा जारी किया गया था 12 अप्रैल, 1991 को यू. सी. ओ. बाटिक प्रमुख के पक्ष में अपीलार्थी कार्यालय में इसके विपरीत हस्ताक्षर करें।

19. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि यह था कि केवल तभी जब अभियुक्त को पता चला कि पूछताछ हो रही थी। यू. सी. ओ. बैंक के मुख्य कार्यालय द्वारा प्रतिभूतियों पर ब्याज का जमा न होने के कारण हुए नुकसान के लिए प्रश्न, अभियुक्तों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से लेन-देन को छिपाने की कोशिश की और श्रेय दिया यूको बैंक के मुख्य कार्यालय में चार लेन-देन होते हैं। ये लेन-देन हैंः

(क) 15 जुलाई, 1991 भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ 11.5 प्रतिशत 2009 रु. 2 करोड की कीमत। यूको बैंक के एस. जी. एल. ए/सी. नं. बीवाईएसएल 065 (दलालों का खाता) से एसजीएल ए/सी नंबर 032 (यूको बैंक का अपना खाता) (ईएक्सटी 245) में हस्तांतरित।

(ख) 21 अक्टूबर, 1991 भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ 11.5 प्रतिशत 2009 अभियुक्त से आई. डी.1 करोड़ उनके राज्य में भारतीय स्टेट बैंक का खाता संख्या 3 में हस्तांतरित।

(ग) 21 अक्टूबर, 1991 फिर से भारत सरकार को हस्तांतरित किया गया प्रतिभूतियाँ 11.5 प्रतिशत 2009 से रू 17 करोड़ की आरोपी 3 का स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र खाता यूको बैंक के खाता संख्या 065 (ईएक्सटी 272)।

(घ) 25 अक्टूबर, 1991 अंत में ये भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ 11.5 प्रतिशत 2009 यू. सी. ओ. से स्थानांतरित किया गया है बैंक का खाता संख्या 065 उसके खाता संख्या 032 पर(एक्स. 282)।

20. उसके तर्क को आगे बढ़ाने के लिए कि आरोपी में उन लेन-देनों को छिपाने की प्रक्रिया विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया कि अवैध कृत्यों के बारे में यूको बैंक के मुख्य कार्यालय से कोई निर्देश नहीं मिलने के बावजूद, अभियुक्त-अपीलार्थी ने रिजर्व बैंक को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया खाता संख्या 065 से खाते में 2 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियाँ सं. 032 (ऊपर दिए गए लेन-देन श्कश् पर पर्दा डालना) एक लोक सेवक के रूप में अपने पद का खुलेआम दुरुपयोग कर रहा है। साजिश की श्रृंखला को साबित करने के लिए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमें एक्स्ट के माध्यम से ले लिया। 277 जो दिखाता है कि त्े.17 करोड़ की प्रतिभूतियाँ राज्य से हस्तांतरित की गई थीं अभियुक्त संख्या 3 95 के खाते से बैंक ऑफ इंडिया (हर्षद मेहता) 21 अक्टूबर, 1991 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सौराष्ट्र (हर्षद मेहता का एक और खाता) और उसी दिन उन्हें फिर से स्टेट बैंक से

स्थानांतरित कर दिया गया। सौराष्ट्र से यूको बैंक एस. जी. एल. खाता संख्या 065 (अतिरिक्त। 272) और फिर 25 अक्टूबर, 1991 को यूको बैंक एस. जी. एल. खाता संख्या 032 (अतिरिक्त। 282) यूको बैंक से किसी भी निर्देश के बिना मुख्य कार्यालय। इस तरह, आरोपी, प्रत्येक के साथ मिलीभगत में अन्य ने यूको बैंक के मुख्य कार्यालय खाते को छिपाने की कोशिश की।

21. साजिश की महत्वपूर्ण कड़ी पर प्रकाश डालते हुए यूको बैंक के धन का दुरुपयोग करने का आरोपी स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को करोड़ रुपये हैदराबाद, हालाँकि ये प्रतिभूतियाँ वास्तव में उनकी नहीं थीं। तदनुसार, 5 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियाँ (अतिरिक्त 235) थे यूको बैंक से किसी भी निर्देश के बिना यूको बैंक एसजीएल खाता संख्या 065 से स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद को हस्तांतरित किया गया। बैंकर का चेक दिनांक 1 जुलाई, 1991 (एक्स. 678) उनके खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद से प्राप्त प्रतिभूतियाँ, यूको बैंक के पक्ष में रुपये. 5,07,195,62.22 (ब्याज सहित) में जमा किए गए थे अभियुक्त सं. 3 (हर्षद मेहता) का लेखा। इसी प्रकार, उसी दिन यानी 1 जुलाई, 1991 को बिना किसी यूको बैंक के निर्देश के रू10 करोड़ की प्रतिभूतियाँ (अतिरिक्त 240) से यूको बैंक का एस. जी. एल. खाता संख्या 065, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को हस्तांतरित किया गया था।

22. विद्वान वरिष्ठ वकील ने अंततः प्रस्तुत किया कि अभियुक्त को दोषी ठहराने में कोई गलती की। इसलिए वह, प्रार्थना की कि विवादित निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

23. दोनों पक्षों की सलाह को हमारे सामने रखे गए विशाल अभिलेख के माध्यम से लंबे समय तक सुना और चला गया जिससे विचार के लिए आता है कि क्या विद्वान न्यायाधीश विशेष अदालत अभियुक्त को उन अपराधों के लिए दोषी ठहराने में सही थी जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया है और क्या अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे साबित किया है?

24. दोनों पक्षों के तर्क के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि यह अभियुक्त का विशिष्ट बचाव है कि बिल्कुल कथित मामले में उसका कोई मकसद या इरादा नहीं है। लेन-देन और यदि कुछ भी किया जाता है, तो यह विशुद्ध रूप से एक लिपिक है। सरासर गलती। निश्चित रूप से उनका कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है कोई धोखाधड़ी या अपराध करना। अनियमितताओं पर ध्यान दिया जो हुआ है, उसने एक राशि खाता न.065 से खाते न.032 में 2 करोड़ रुपय हस्तांतरित करने के लिए कदम उठाए हैं। वह किसी साजिश में शामिल नहीं है या लेन-देन से लाभान्वित नहीं है और विद्वान न्यायाधीश इसकी सराहना करने में विफल रहे हैं। अपने उचित परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य और अभियुक्त को दोषी ठहराने में खुद को गुमराह

किया। जबकि सी. बी. आई. की ओर से, विशेष न्यायालय के फैसले का समर्थन करने वाली दलीलें आगे बढ़ा दी गईं।

25. सी. बी. आई. ने यह साबित करने के लिए भारी सबूत पेश किए हैं अभियुक्त का अपराध। पूरा मुद्दा इस तथ्य के इर्द-गिर्द घूमता है कि क्या स्विच में आरोपी की कोई भूमिका है। लेन-देन खाता और क्या वह भुगतान कर रहा था एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में कर्तव्य और क्या यह एक वास्तविक गलती है क्योंकि वह होने का दावा करता है।

26. यह रिकॉर्ड से और पूरी तरह से दिखाई देता है। अप्रैल 1991 के बीच हुई घटनाओं की जांच और अक्टूबर 1991, हम समझते हैं कि 22 मार्च, 1991 को किस तारीख को यूको बैंक की 11.5 प्रतिशत 2009 प्रतिभूतियों को अंकित किया गया था रुपये का मूल्य 20 करोड़ रुपये इंडियन बैंक को बेचे गए, यूको बैंक ने इंडियन बैंक से समान मूल्य की प्रतिभूतियां खरीदी हैं। 11.5 प्रतिशत 2006 अपने एस. जी. एल. खाता संख्या 032 के लिए जी. ओ. आई. प्रतिभूति। 5 अप्रैल, 1991 को उपरोक्त दोनों लेनदेन को उलट दिया गया था। नतीजतन, यूको बैंक का खाता संख्या 032 वापस मिल जाना चाहिए था। उपरोक्त प्रतिभूतियाँ, लेकिन वही गलत तरीके से थीं यूको बैंक के एस. जी. एल. खाता संख्या 065 में हस्तांतरित किया गया, दलालों द्वारा संचालित। उस समय आरोपी नंबर 3 को छोड़कर यूको बैंक खाता संख्या 065 का संचालन करने वाले सभी

दलालों के लेन-देन बंद हो गए थे। इसे अपने पास ले जाना यू. सी. ओ. बैंक में रखी प्रतिभूतियों से लाभ खाता संख्या 062, रू 15 करोड़ की प्रतिभूतियाँ बेची गई हैं। सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद को उन प्रतिभूतियों के निर्वहन यूको बैंक के पक्ष में रू 5,07,195,62.22 (ब्याज सहित) की राशि के लिए जारी किया गया बैंकर चैक आरोपी नम्बर 3 (हर्षद मेहता) के खाते में जमा किया गया।

27. टेलेक्स संदेश दिनांकित 23.3.1991 (एक्स्ट 287) और 6.4.1991 (एक्स. 466) स्पष्ट रूप से बताता है कि यूको बैंक का मुख्य कार्यालय अपने खाते (032) के लिए लेनदेन बदलने का निर्देश दिया गया। दिनांक 13 अप्रैल, 1991 का संचार (एक्स. 300) अभियुक्त द्वारा भेजा गया। 1 और 2 एक साधारण गलती के रूप में नहीं माना जा सकता है परिणामी घटनाओं पर विचार करना। हमने अपना दिया है उक्त संचार के लिए चिंतित और पूरी तरह से अवलोकन (एक्स. 300) और पाया कि संचार की तैयारी और विचाराधीन प्रतिभूतियों से संबंधित प्रविष्टि भी लिखी गई है अभियुक्त सं. 1 द्वारा-यहाँ स्वयं अपीलार्थी। प्रविष्टि यूको बैंक के खाते में प्रतिभूतियों को स्थानांतरित करने का संकेत देती है। सं. 065 (दलालों का खाता) दो अन्य प्रविष्टियों के साथ अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित जो वास्तव में हस्तांतरण के लिए थीं यूको बैंक के खाता संख्या 065 में। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। अपीलार्थी की याचिका को स्वीकार करें कि यह केवल एक लिपिकीय गलती थी कि खाता संख्या 032 को बंद कर दिया गया था

और खाता संख्या 065 अभियुक्त नं. 2 द्वारा बरकरार रखा गया था। प्रतिभूतियों का समावेश अपीलार्थी द्वारा अपनी लिखावट में उक्त संचार में प्रश्न इस तथ्य को स्थापित करता है कि अपीलार्थी ने जानबूझकर और गलत उद्देश्य से संचार तैयार किया था।

28. अभियुक्त द्वारा दावा किया गया था कि उसने 2 करोड़ रुपये की राशि खाता न.065 से खाता न.032 तक बिना किसी लेनदेन के स्थानांतरण कर दिया है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मुख्य कार्यालय की पूछताछ से बचने के लिए, आरोपी बिना किसी लेन-देन के पैसे हस्तांतरित करने का विकल्प चुना है और आरोपी के आचरण को प्रदर्शित करता है। यू. सी. ओ. के बीच लेनदेन बदलने से संबंधित सभी दस्तावेज बैंक और इंडियन बैंक पर अभियुक्तों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते वे अच्छी तरह से जानते थे कि ये प्रतिभूतियाँ हैं यूको बैंक के मुख्य कार्यालय द्वारा खरीदा गया, जो किसी भी समय कल्पना के विस्तार को गलती या निरीक्षण के रूप में नहीं कहा जा सकता है, और सबसे बढ़कर, डेबिट और क्रेडिट वाउचर विचाराधीन लेन-देन अभियुक्त द्वारा किया गया था। 12.4.1991 को इंडियन बैंक की बैंक रसीद कज. 5-4-1991 (एक्स. 299) था छुट्टी दे दी गई और ए1 ने बैंक रसीद के पीछे की ओर हस्ताक्षर किए। लेन-देन बदलने से संबंधित लगभग सभी दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर हैं।

29. हमने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों पर भी गौर किया है। पीडब्लू1- एस नागराजन, वह व्यक्ति जो काम कर रहा था आर. बी. आई. के सार्वजनिक ऋण कार्यालय में प्रासंगिक समय पर, अपने बयान में बताया कि एस. जी. एल. खातों का रखरखाव कैसे किया जाता है। पीडब्लू 2 हरसुखलाल छोटालाल पारेख, यू. सी. ओ. के पूर्व प्रबंधक बैंक की हमाम स्ट्रीट शाखा ने जोर देकर कहा कि जब लेनदेन एसजीएल खातों पर किए जाते हैं, तो आवश्यक है। निर्देश प्राप्त किए जाते हैं। प्रतिभूति विभाग द्वारा संबंधित ब्रोकर से हमाम स्ट्रीट शाखा। मान लीजिए, पीडब्लू1 द्वारा बताए अनुसार एसजीएल खातों से निपटने की प्रक्रिया और विचाराधीन प्रतिभूतियों के मामले में पीडब्लू2 का पालन नहीं किया गया है। अभिलेख पर सामग्री स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि यूको बैंक एसजीएल खाता संख्या के खाते में गलत प्रविष्टि 065 हर्षद मेहता (अभियुक्त सं 3) एक अनजाने में त्रुटि के परिणामस्वरूप नहीं हुआ था, लेकिन एक दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया सुनियोजित कुकर्म था।

30. मामले के पूरे परिदृश्य को देखते हुए, वहाँ है हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि आरोपी, जो बैंकिंग गतिविधियों और एस. जी. आई. से अच्छी तरह से परिचित है। लेन-देन, गलत बनाए गए दस्तावेज और प्रावधानों के विपरीत कार्य किया और प्रतिबद्ध किया गया अवैध कार्य जो अभिलेख के सामने बड़े पैमाने पर लिखे जाते हैं। यह हो चुका है विचारण न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि अभियुक्त संख्या

1 पहले ही दो मामलों में दोषी ठहराया गया और दो और मामले लंबित हैं। एक मामले में, वह कुछ समय के लिए कारावास से गुजरे हैं। एक वर्ष और दूसरे मामले में, 9 महीने की अवधि के लिए कारावास, जो अभियुक्त के आचरण को दर्शाता है, हालांकि यह हमारे निष्कर्ष का आधार नहीं है। इसलिए, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता अभियुक्तों के लाभ के लिए एसजीएल प्रतिभूतियों के व्यापार को सुविधाजनक बनाने की साजिश का हिस्सा था। नंबर 3 (हर्षद मेहता) और इस प्रक्रिया में, अपने अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया स्थिति और बैंकिंग कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन किया। तथ्य और मामले की परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से भागीदारी को दर्शाती हैं आपराधिक कृत्यों में अपीलार्थी और अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग। हमारी राय में, अभियोजन पक्ष ने आरोपी के बीच सांठगांठ को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है। अपराधों के तत्व जिसके लिए अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है, यह भी अभियोजन पक्ष द्वारा विशाल दस्तावेजी साक्ष्य के साथ-साथ मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करके सभी उचित संदेह से परे स्थापित किया गया है।

31. पूर्वगामी कारणों से, हम इसमें कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि विद्वत विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित निर्णय में हमारे हस्तक्षेप का आह्वान करने वाली अपील। नतीजतन, अपील विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है। 21 फरवरी, 2005 के इस न्यायालय के आदेश द्वारा अपील के लंबित रहने के दौरान कारावास निलंबित रहा। उक्त

आदेश एतद्द्वारा वापस लिया जाता है। अपीलार्थी को कारावास अवधि पूरी करने के लिए तुरंत हिरासत में लिया जा सकता है।

कल्पनाके.त्रिपाठी याचिका खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवाद न्यायिक अधिकारी अजय सिंगारिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।